

# भारत और मुक्त व्यापार समझौते

# प्रलिम्सि के लियै:

मुक्त व्यापार समझौता (FTA), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), CECPA, SAFTA, APTA

# मेन्स के लिये:

भारत के लिये मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से संबंधति मुद्दे, भारत के वभिनिन व्यापार समझौते और आर्थिक विकास में इनकी भूमकिा, भारत-इज़रायल संबंध, भारत की विदेशों व्यापार नीति।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणजि्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन हेतु इजरायल के साथ वार्ता कर रहा है। The Visio

यह घोषणा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ के साथ मेल खाती है

# प्रमुख बद्धि

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
  - ॰ यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।
  - ॰ एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहूत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।
  - ॰ मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- भारत तथा मुक्त व्यापार समझौते:
  - ॰ नवंबर 2019 में भारत के क्षेतरीय वयापक आरथिक भागीदारी (RCEP) से बाहर होने के बाद, 15 सदस्यीय FTA समूह जिसमें जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, भारत के लिये निष्क्रिय हो गया।
  - लेकिन मई 2021 में यह घोषणा हुई कि भारत-यूरोपीय संघ की वार्ता, जो 2013 से रुकी हुई थी, फिर से शुरू की जाएगी।
    - कार्य संबंधी इन विभानन पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिये दोनों पक्ष अब आंतरिक तैयारियों में लगे हुए हैं।
  - ॰ भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौत<mark>ों को लेकर सं</mark>युक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ बातचीत की जा रही है।
  - ॰ यूएई के साथ यह समझौता 'अं<mark>तमि रूप देने</mark> के करीब' था जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए 'बहुत उन्**नत चरण' में** था ।
- भारत के अन्य महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौते:
  - ॰ भारत और मॉरीश<mark>स के बीच व्या</mark>पक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)।
  - दक्षणि एश्रिया तरजीही व्यापार समझौता (SAPTA): यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये 1995 में लागू हुआ
  - ॰ दक्षणि एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा): यह मुक्त व्यापार समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर, सामान तक ही सीमति है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए):
    - बैंकाक समझौता, यह एक तरजीही टैरिफ व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
- भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधी मुद्दे:
  - ॰ **खराब वनिरिमाण क्षेत्र:** हाल की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वनिरिमाण क्षेत्र की हस्सिदारी 14% है।
  - ॰ जर्मनी, अमेरिका, दक्षणि कोरिया और जापान जैसे उन्नत और विकसित देशों के तुलनीय आँकड़े क्रमशः 19%, 11%, 25% और 21%
    - चीन, तुर्की, इंडोनेशिया, रूस, ब्राज़ील जैसे उभरते और विकासशील देशों के लिये संबंधित आँकड़े क्रमशः 27%, 19%, 20%, 13%, 9% हैं तथा कम आय वाले देशों के लिये यह हिस्सा 8% है।

- प्रतिकूल FTA's: पिछले एक दशक में भारत ने **दक्षणि पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान),** कोरिया गणराज्य, जापान और मलेशिया के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए।
  - हालाँकि काफी हद तक यह माना जाता है कि भारत के व्यापार भागीदारों को भारत की तुलना में इन समझौतों से अधिक लाभ हुआ है।
- ॰ संरक्षणवाद: आत्मनरिभर भारत अभियान ने इस विचार को और बढ़ा दिया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

## भारत-इज़रायल संबंध

#### • ऐतहासिक संबंध:

- ॰ दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग 1962 के **भारत-चीन युद्ध** के दौरान शुरू हुआ।
- ॰ 1965 में इज़रायल ने **पाकसितान के खिलाफ युदध** में भारत को M-58 160-mm मोर्टार गोला बार्द की आपूरति की।
- ॰ यह उन कुछ देशों में से एक था जिसने 1998 में **भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों** की निदा नहीं करने का फैसला किया था।

#### आर्थिक:

- ॰ भारत एशयाि में इज़राइल का तीसरा सबसे बड़ा वयापार भागीदार है और विशव सतर पर सातवां सबसे बड़ा वयापार भागीदार है।
- ॰ दोनों देशों के बीच वर्तमान में 4.14 बलियिन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है (अप्रैल 2020 फरवरी 2021), एक ऐसा ऑंकड़ा जिसमें रक्षा वयापार शामिल नहीं है जो बढ़ रहा है।
- ॰ इजरायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवश किया है और भारत में अनसंधान एवं विकास केंद्र या उतपादन इकाइयां सथापित करने पर धयान केंद्रित कर रही हैं।
- इज़रायल-भारत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास औ<u>र तकनीकी नवाचार कोष (I4F)</u> से पहले अनुदान प्राप्तकर्त्ता की घोषणा जुलाई 2018 में की गई थी, जिसमें कुशल जल उपयोग, संचार बुनियादी ढाँचे में सुधार, सौर ऊर्जा उपयोग के माध्यम से भारतीयों और इज़रायलियों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु काम करने वाली कंपनियों को शामिल किया गया है।
  - इस फंड का उददेश्य इज़रायली उदयमियों को भारतीय बाज़ार में प्रवेश कराने में मदद करना है।

#### • रक्षाः

- ॰ इज़रायल लगभग दो दशकों से भारत के शीर्ष चार हथियार आपूरतिकर्त्ताओं में <mark>से ए</mark>क है, <mark>हर वर्ष लगभग 1 बलियि</mark>न अमेरिकी डॉलर की सैन्य बिक्री होती है।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल किया है, इसमें काल्कन AWACS (हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) तथा हेरॉन, सर्चर-द्वितीय तथा हारोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों और स्पाइडर विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
- ॰ अंधिग्रिहण में कई इंज़रायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्<mark>री भी</mark> शाम<mark>लि है,</mark> जिसमें 'पायथन' और 'डर्बी' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर 'क्रिस्टल मैज़' तथा स्पाइस-2000 बम शामिल हैं।
- भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में, दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक दस-वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं।

#### कृषः:

॰ भारत और इज़रायल ने कृषि सहयोग में विकास के लिय<u>े "तीन वर्षीय कारय योजना समझौते"</u> पर हस्ताक्षर किये हैं।

#### कोवडि-19 प्रतिक्रिया:

॰ वर्ष 2020 में एक इज़रायली टीम बहु-आयामी मशिन के साथ भारत पहुँची, जिसका कोड नेम 'ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस' था, इसे कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने हेतु बनाया गया था।



## आगे की राह

- यह देखते हुए कि भारत किसी बड़े-व्यापार सौदे का पक्ष नहीं है, यह एक सकारात्मक व्यापार नीति एजेंडे का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होगा ।
- भारत के व्यापार नीति ढाँचे को आर्थिक सुधारों द्वारा समर्थित होना चाहिये, जिसके परिणामस्वरूप यह एक खुली, प्रतिस्पिर्द्धात्मक और तकनीकी रूप से नवीन भारतीय अर्थव्यवस्था हो।
- राष्ट्रवाद, देशीवाद और संरक्षणवाद लोगों की इस भावना का फायदा उठाते हैं कि उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है और उन्हें व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है।
- इसलिये हमें आर्थिक नेटवर्क में सार्वभौमिक समावेश सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने और बेहतरी के अवसरों को प्राप्त करने की अनुमतिदेता है।

# स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-free-trade-agreements